

Title: Regarding Disinvestment of Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (HPCL) and Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL).

MR. SPEAKER: Hon. Members, there is one Calling Attention notice today. Since we have little time, we can take it up after Lunch and I would like to take up 'Zero Hour' now, if the House agrees.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. SPEAKER: If the House has agreed to this, then I would take up 'Zero Hour' now.

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, पोटा के बारे में मेरा नोटिस है। **â€** (व्यवधान)

श्री प्रमुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव था। आपने मुझे कहा था कि आप मुझे शून्य-काल में बोलने का अवसर देंगे। **â€** (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रामजी लाल सुमन जी, आप तो जानते हैं कि मैंने पहले श्री प्रभु नाथ सिंह जी का कार्य-स्थगन प्रस्ताव लिया था। इसलिए मैं पहले उनको बोलने के लिए समय दे रहा हूँ। उनके बाद आपको समय दूंगा।

श्री प्रमुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, **â€** (व्यवधान)

MR. SPEAKER: There is only one Calling Attention today and notice for that is given by Shri H.D. Deve Gowda.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, बोटल बंद पेयजल वाला भी एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा हुआ है। इसको कब ले रहे हैं और दे वेगौड़ा जी का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कब लेंगे ? Mr. Speaker, Sir, Calling Attention is always taken up first before the 'Zero Hour'.

MR. SPEAKER: Dr. Vijay Kumar Malhotra, you are right. I am in agreement with you. Shri Deve Gowda's Calling Attention is not being taken up today, but I am going to permit him to speak on that during the 'Zero Hour' and the Calling Attention which I referred to was that of Shri Naresh Puglia. That will be taken up at 2.00 p.m.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : देवेगौड़ा जी का प्रस्ताव कितने बजे लेंगे ?

MR. SPEAKER: I will take it up around 12.45 p.m., after I take up other notices.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : क्या आज ही दोनों होंगे। आज तो एक होगा, दोनों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : आज एक होगा।

MR. SPEAKER: As far as Shri Deve Gowda's submission is concerned, it is a 'Zero Hour' notice and not of Calling Attention.

12.09 hrs.

श्री प्रमुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. के विनिवेश के सवाल पर पूरे देश में मतभेद है। जहां 95 प्रतिशत जनता इसके खिलाफ है वहां सदन में भी विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष के भी कई घटक इस सदन में बोल चुके हैं और वे एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. के विनिवेश के खिलाफ हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में पेट्रोलियम मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने भी अपना प्रतिवेदन दिया था, जिस पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. का विनिवेश करने के संबंध में सदन से अनुमति भी नहीं ली। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि बावजूद इसके एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। देश के सार्वजनिक उपक्रमों में आई.ओ.सी., आई.बी.पी., ओ.एन.जी.सी., एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. आदि प्रमुख तेल कंपनियां हैं। ये सारी मुनाफा कमाने वाली कंपनियां हैं। वर्ष 2001-2002 में एच.पी.सी.एल. ने 173 करोड़ और बी.पी.सी.एल. ने 118 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। इसके बावजूद सरकार मुनाफे वाली कंपनियों का विनिवेश किए जा रही है, जो देश-हित में नहीं है। तेल से जहां उपभोक्ताओं का हित जुड़ा हुआ है वहां देश की सुपेक्षा एवं अन्य हित जुड़े हुए हैं। सरकारी क्षेत्र की ये कंपनियां जहां सामाजिक कार्यों को महत्व देती हैं वहीं निजी कंपनियां अतिरिक्त मुनाफे की दृष्टि से अपना कारोबार करती हैं।

देश में पेट्रोल, डीजल, एल.पी.जी. एवं किरोसिन तेल का मूल्य निर्धारण बराबर एक प्रश्न बना रहता है, जिनका समाधान करने में निजी क्षेत्र खरा नहीं उतर सकता। इसका कारण यह है कि निजी क्षेत्र के सामने सामाजिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा तथा देश हित के प्रति त्याग और बलिदान की भावना नहीं होती, उसे सिर्फ मुनाफे से मतलब होता है। तेल सुरक्षा की व्यवस्था को देखते हुए भंडारण का कार्य अल्प सूचना पर निजी क्षेत्र नहीं कर सकता है। इसका कारण यह है कि सरकार इस पर व्यय नहीं करती बल्कि कम्पनियों ही इस पर व्यय करती हैं। मध्य पूर्व की भयानक स्थिति और पाकिस्तान की सीमा पर तनाव के चलते तेल सुरक्षा की समस्या उभर कर सामने आई है। आज 51 प्रतिशत टर्मिनल और 50 प्रतिशत खुदरा बिक्री केन्द्र एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. के हाथ में है, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 15 दिनों तक तेल रखने में 5000 करोड़ रुपए की लागत आती है। बी.पी.सी.एल. और एच.पी.सी.एल. अत्यधिक भंडारण की व्यवस्था में 550 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं, वहीं निजी क्षेत्र तेल सुरक्षित रखने में सक्षम नहीं हो सकता। हमें 1971 का युद्ध भुलाना नहीं चाहिए। रिलायंस और इसर जैसे निजी क्षेत्र अभी अपनी संरचना खड़ी कर रहे हैं। दूसरी ओर एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. कुशलता पूर्वक अपना उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। वैसी परिस्थिति में एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. का विनिवेश न तो तेल सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित होगा और न ही उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण से उचित होगा।

अध्यक्ष महोदय, हम आपको यह बताना चाहते हैं कि रिलायंस जैसी कम्पनियों के हाथ में आज सरकार खेल रही है और रिलायंस के इशारे पर एच.पी.सी.एल. और

बी.पी.सी.एल. के विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की गई है। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि विनिवेश की प्रक्रिया को तब तक रोका जाए जब तक इस पर सदन में चर्चा करा कर सदन से अनुमति न ले ली जाए। बिना सदन की अनुमति के एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. के विनिवेश की प्रक्रिया देशहित और देश की सुरक्षा के हित में नहीं है। इसलिए आप इस गंभीर सवाल पर सदन में चर्चा को शीघ्र लें और बिना चर्चा के इस सदन में इस विनिवेश की प्रक्रिया पर प्रतिबंध लगाने का काम करें।^{â€} (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, आप सदन की स्थिति देख लीजिए।^{â€} (व्यवधान) हमारी जानकारी के अनुसार कैबिनेट में भी बहुसंख्यक मंत्री विनिवेश प्रक्रिया के विरोध में हैं। पेट्रोलियम मिनिस्टर भी एच.पी.सी.एल. और विनिवेश प्रक्रिया के विरोध में थे, लेकिन उन पर दबाव डाला गया, उनकी जुबान बंद कराई गई। यह देश हित में नहीं है। हम आपसे दोबारा निवेदन करते हैं कि इस सवाल पर सदन में चर्चा कराई जाए।^{â€} (व्यवधान)

SHRI BASU DEB ACHARIA (BANKURA): Sir, this is a very important issue. ...*(Interruptions)* They are bypassing the Parliament. ...*(Interruptions)* The Government has taken a decision. ...*(Interruptions)* We have given notice under Rule 184. ...*(Interruptions)*

MR. SPEAKER: Please sit down.

...*(Interruptions)*

MR. SPEAKER: This issue is, no doubt, an important one. But today, when the House started, I received a notice for Adjournment Motion. It had three names. Therefore, I have permitted Shri Prabhunath Singh to speak. देवेन्द्र प्रसाद जी, आप भी केवल एक मिनट बोल सकते हैं, मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे सकता हूँ। Thereafter, Shri Jha will speak for a minute. Other Members will not be allowed to speak because there is going to be a discussion on this issue.

SHRI BASU DEB ACHARIA : I have given a notice. ...*(Interruptions)*

MR. SPEAKER: There is going to be a discussion.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): We want full discussion, Sir.

MR. SPEAKER: Yes; full discussion will be allowed. The Business Advisory Committee will decide the date.

...*(Interruptions)*

MR. SPEAKER: You have to finish in a minute's time because the procedure is different.

...*(Interruptions)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं,^{â€} (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आप बोल चुके हैं।

^{â€} (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please sit down.

...*(Interruptions)*

MR. SPEAKER: I will take the necessary care about the subject.

...*(Interruptions)*

MR. SPEAKER: Please sit down. Let there be silence in the House.

^{â€} (व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, चर्चा के पहले कह दिया जाए कि जब तक चर्चा समाप्त नहीं हो जाती है, इस पर सदन से सहमति नहीं ले ली जाती है तब तक विनिवेश प्रक्रिया रोकी जाए।^{â€} (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यह विषय न केवल राष्ट्रीय महत्व का है, बल्कि देश भर में करोड़ों उपभोक्ताओं का और जो सामाजिक वेलफेयर का काम है, उसके भी हित में है। एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल. के विनिवेश की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, ये सारी कम्पनियां मुनाफे में हैं। प्रोफिटेबल कम्पनियों और अंडरटेकिंग्स को जिस तरह से विनिवेश की प्रक्रिया में डाला जा रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि पूरा देश इस विनिवेश शब्द से गुमराह हो रहा है। यह जो डिसइन्वैस्टमेंट वर्ड है, इससे आज करोड़ों लोग जो गांवों में रहते हैं, जो निरक्षर हैं, पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं, वे कहते हैं कि यह विनिवेश क्या है। हम तो सबसे पहले आपसे यह अनुरोध करेंगे कि इस विनिवेश मंत्रालय का नाम बदलकर राष्ट्रीय सम्पत्ति बेचो मंत्रालय रख दिया जाये, ताकि जनता में भ्रम नहीं रहे। आज पूरे देश की जनता में भ्रम है।

अभी प्रभुनाथ सिंह जी ने जिक्र किया कि तेल से जुड़े सरकारी उपक्रम जहां एक तरफ उपभोक्ता के हित से जुड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ देश की सुरक्षा और वेलफेयर के काम में इनका महत्व है। क्या निजी कम्पनियां इस वेलफेयर के काम को, सुरक्षा के काम को उस तरह की प्रायर्टी देंगी, क्या इसकी कोई गारण्टी है? मैं अन्तिम बात कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। इस देश में गरीबी की रेखा के नीचे जो 32 करोड़ लोग हैं, वे कैरोसीन तेल का उपयोग करते हैं, एल.पी.जी. का उपयोग तो

मध्यम वर्ग के लोग करते हैं, तो कैरोसीन तेल का उपयोग करने वाले लोगों के लिए मूल्य निर्धारण की क्या गारण्टी होगी, जब सब विनिवेश में चला जायेगा, जब बी.पी.सी.एल. को बेच दिया जायेगा? मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि इसका समाधान करने के लिए निजी क्षेत्र खरा नहीं उतर सकता है। (व्यवधान)

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : इस पर मेरा भी नाम है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इसीलिए मेरा स्पष्ट निवेदन है कि 15 दिन तक तेल रखने में पांच हजार करोड़ रुपये खर्च होते हैं, इसलिए तेल रखने में कोई निजी क्षेत्र की कम्पनी सक्षम नहीं हो सकती है। 1971 के पाकिस्तान से युद्ध को भी याद रखना चाहिए कि किस तरह से तेल को सुरक्षित रखा जाता है। ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर रिलायंस कम्पनी के पास अभी नहीं है, यह इन्फ्रास्ट्रक्चर अभी तक रिलायंस कम्पनी खड़ा नहीं कर सकी है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इतना समय नहीं दे सकता।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मेरा स्पष्ट निवेदन है कि सरकार रिलायंस कम्पनी के हाथ में इस देश को न बेचे और इस मंत्रालय का नाम राष्ट्रीय सम्पत्ति बेचो मंत्रालय रखा जाये।

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्य प्रभुनाथ सिंह जी ने और देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने बातें कही हैं, उससे मैं अक्षरतः अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ। आज देश की जो परिस्थिति है और कल जो संसद में माननीय मंत्री जी रूपचन्द्र पाल जी के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, उनके उत्तर के बाद भ्रम और बढ़ गया है। पार्लियामेंट की एथॉरिटी को, संसद की गरिमा को ये ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मात्र एक कम्पनी को फायदा पहुंचाने के लिए यह सरकार पूरी तरह से डिटरमिंड है और देश की गरिमा, देश की सुरक्षा, गरीबों को हक के विपरीत ये लोग उसके हाथ में खेल रहे हैं। यही कारण है, ठीक ही सवाल पूछा गया है, हम जानना चाहते हैं, यह संसद हैं, मंत्री जी बतायें कि किस परिस्थिति में पहले इसका विरोध किया था और कौन सा कारण हुआ कि जाकर सरैण्डर कर दिया? कौन सी परिस्थिति हुई, क्या मंत्री पद के लालच में सरैण्डर हो गये कि पद गंवाना पड़ेगा या मुंह बन्द किया है या किसी से कुछ मिला? किस कारण से इस बात का विरोध किया? कल भी प्रश्न उठा था कि एटार्नी जनरल ने प्रभाव में आकर अपना ओपिनियन दिया है, उन्हें सदन में बुलाया जाये और इस कार्रवाई को स्थगित किया जाये और जब तक संसद की मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक इस पर आगे की कार्रवाई रोकी जाये।

MR. SPEAKER: The Members have expressed their sentiments on this important issue. Would the Minister of Petroleum like to say something on this issue?

श्री सोमनाथ चटर्जी : उनकी नौकरी चली जायेगी।

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI RAM NAIK): Sir, you have already said that it will be taken into account in the Business Advisory Committee meeting.

In that discussion, it will be decided. We will be taking a decision.

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, इनका क्या विचार है, यह बतायें। (व्यवधान)

SHRI SHIVRAJ V. PATIL (LATUR): Let the Minister reply to the points raised by all the Parties. Only a few Members have raised it and this is a subject on which the Government should have come to Parliament asking for the opinion of the Members of Parliament. They are not coming. You are very kindly allowing this discussion. Let all the points come and then we will ask the Minister to reply.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर हमारा भी नोटिस है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उसे बाद में लूंगा।

...(व्यवधान)

SHRI P.H. PANDIAN (TIRUNELVELI): Sir, this is in continuation of what Shri Shivraj V. Patil said....(Interruptions)

MR. SPEAKER: I am sorry.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: You are all senior Members. If you want to speak on anything, you can give a notice and then come before the House.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: I have not opened this subject for a debate. Please sit down.

...(Interruptions)

अध्यक्ष महोदय : रामजी लाल सुमन जी, अगर आप नहीं बोलेंगे तो मैं दूसरा विषय ले लूंगा।

...(व्यवधान)

MR. SPEAKER: What are you doing? Nothing should be taken on record except what Shri Ramji Lal Suman speaks. Now there should be discipline in the House.

(Interruptions)*

MR. SPEAKER: You can say all this when there is debate.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: During the debate, I will give you permission to speak.

SHRI P.H. PANDIAN : I am not on the merit or demerit of the case. Yesterday, the Minister said that it was governed under the Companies Act. It is a Public Sector Undertaking. All the Public Sector Undertakings are the agents of the Government as defined under article 12. A nine-member Bench of the Supreme Court has said recently that all the Public Sector Undertakings are the agents of the Government. So, when a Public Sector Undertaking is disinvested, it is for the Government to get the sanction of Parliament. You know the Magna Carta that the tax has been levied without the authority of the Crown. So also, money cannot be appropriated without the sanction of Parliament. So, the sanction of Parliament is important.â€ (Interruptions)

MR. SPEAKER: If the Parliament wants to maintain the supremacy of the House, then the Members should also be disciplined. Please sit down.

...(Interruptions)

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमें आपके द्वारा यह एश्योरेंस चाहिए कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम को नहीं बेचा जायेगा।â€ (व्यवधान)

* Not Recorded.

MR. SPEAKER: Shri Pandian, is it your walkout?

SHRI P.H. PANDIAN : No, Sir.

श्री प्रमुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने सदन की भावना को देखा है। इस तरफ, उस तरफ और पीछे बैठे लोग जो कुछ कह रहे हैं, वह ठीक कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि आपका नियमन होता कि कम से कम जब तक सदन से इस पर अनुमति नहीं ले ली जाये तब तक इस प्रक्रिया को स्थगित किया जाये। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सदन का सत्र चल रहा है और उधर विनिवेश की प्रक्रिया शुरू हो गयी है।â€ (व्यवधान) यह देश बेचने की स्थिति है। इस पर आपको नियमन देना चाहिए। आप सदन की भावना देख रहे हैं।â€ (व्यवधान) चारों तरफ से लोग कह रहे हैं कि यह गलत हो रहा है, देश हित में नहीं हो रहा है।â€ (व्यवधान) यह देश की सुरक्षा के विपरीत हो रहा है।â€ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रमुनाथ सिंह जी, आप प्रश्न उठाते हैं और मुझे बोलने नहीं देते, यह कैसे चलेगा ?

...(व्यवधान)

श्री प्रमुनाथ सिंह : हम आपको सुनना चाहते हैं।â€ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न उठाया तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आप मुझे जवाब तो देने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिये। जिसका प्रश्न है, उसको मैं जवाब दे रहा हूँ। ... (व्यवधान)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : The Government should respond.

SHRI CHANDRA SHEKHAR (BALLIA, U.P.): Mr. Speaker, Sir, the House will like to be guided by you. Everyday, the Ministers are making statements that they will sell away the Public Sector Undertakings, whether they are profit-making or loss-making. They also claim that they have the authority to do anything they like without consulting or discussing the matter in Parliament. It is not the question of one individual case. The question raised is about the authority of this Parliament.

If Ministers flout the authority of Parliament, I shall like your guidance what hon. Members should do, whether they should wait for the discussion when the Ministers sell away the whole country.

I would not have raised this matter. A PIL has been filed in the Supreme Court and the Government has come out with a statement that disinvestment was started by the Government when I was the Prime Minister of this country. At that time, I had specifically said that only 20 per cent of the loss making companies should be sold away to the financial institutions in order to improve the management and financial condition of those companies. This Government is going on spreading falsehood. This Government is going on challenging the authority of Parliament.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: The Minister is here. The Party Leader is also here. Please sit down.

...(Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : The discussion should be held under Rule 184. ...(Interruptions)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, एचपीसीएल और बीपीसीएल को जो बेचने की बात हो रही है, पूरे देश और दुनिया को जानकारी है कि ये प्रॉफिट मेकिंग कम्पनियां हैं और सरकार की तरफ से यह स्पष्ट नहीं किया जा रहा है कि प्रॉफिट मेकिंग इन कम्पनियों को बेचने के लिए ये क्यों उतारू हैं? (व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : अध्यक्ष जी, आप इस विषय पर पूरे दिन डिसकशन करा लीजिए लेकिन ज़ीरो ऑवर में केवल एक विषय ही चलता रहे और दूसरे विषय या अति आवश्यक या जो ध्यानाकर्षण तथा और भी दूसरे विषय हैं, वे नहीं आएँ, यह तो नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह बीच में कैसे बोल सकते हैं? रघुवंश प्रसाद जी का ज़ीरो ऑवर में नोटिस है।

(व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : सर, ज़ीरो ऑवर में और भी नोटिस हैं, हमारा भी नोटिस ज़ीरो ऑवर में है, उसको भी लेना चाहिए। (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, देश भर में यह बात हो चुकी है कि ओएनजीसी ने भी जो सरकारी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं, खरीदने के लिए पैटीशन दी थी। (व्यवधान) लेकिन ओएनजीसी को रोका गया कि ओएनजीसी इसमें हिस्सा नहीं ले सकता। इससे देश में यह आशंका बढ़ गई है कि सरकारी कंपनी को खरीदने की इजाजत नहीं है। केवल रिलायंस को देने के लिए यह सब हो रहा है। यह भी बार-बार मंत्री वक्तव्य दे रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल को बुलाने का प्रश्न नहीं उठता। जब जब सदन में सवाल उठा है, नियम यह कहता है कि अटॉर्नी जनरल स्वयं आ सकते हैं अथवा सरकार के बुलाने से आ सकते हैं अथवा आपके निदेश पर आ सकते हैं, आपके आग्रह करने पर आ सकते हैं। पूर्व में चार बार अध्यक्ष महोदय के निदेश पर अटॉर्नी जनरल सदन में हाजिर हुए हैं। आप सदन के संरक्षक हैं और कांस्टीट्यूशनल राइट जो हमारा पार्लियामेंट का राइट है, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है जबकि संविधान कहता है कि सरकार इस पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। उस क्लॉज को भी चैलेंज किया जा रहा है। सरकार को मनमानी करने की इजाजत दे दी गई है और अटॉर्नी जनरल को यह कहने का राइट है और पार्लियामेंट की अवमानना की जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सब तो आपने कल कहा है। मल्होत्रा जी, आप बोलिए।

(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : पूर्व में भी एक अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि नहीं, यह सब पार्लियामेंट में डिसकस होना चाहिए और नियम कहता है कि 'कॉल एंड शकधर' में महा न्यायवादी कब-कब आ सकते हैं। स्थिति यह है कि महा न्यायवादी स्वयं सभा में या सभा द्वारा पारित किसी प्रस्ताव पर या सरकार के अनुरोध पर या यदि सभा के समक्ष किसी मामले पर अध्यक्ष उसकी बात सुनना चाहे तो अध्यक्ष के अनुरोध पर वह उपस्थित हो सकते हैं। चार बार उदाहरण हैं। इसीलिए यह पार्लियामेंट के प्रोपराइटी और उसके अधिकार का प्रश्न है। उसकी सोवरीनिटी को चैलेंज किया जा रहा है। सदन की भावना है, इसलिए आप ही सदन की गरिमा बचा सकते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि महा न्यायवादी ने पार्लियामेंट के प्रति जो इस तरह का उल्टा-पुल्टा बयान दिया है, उनको सदन में हाजिर कराया जाए जिससे सदन में हम लोग उनसे स्पटीकरण पूछेंगे ताकि जो यह बेचने की बात हो रही है, इस पर रोक लग सके। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, आप खड़े हो जाइए तभी वह बैठेंगे, नहीं तो वह नहीं बैठेंगे।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, यहां पर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में सभी दलों के नेताओं ने तय किया था कि डिसइंवेस्टमेंट पर एक दिन पूरी बहस होगी और इसमें मैरिट के अंदर बहुत सी चीजों के बारे में तय हो जाएगा। हर सेशन में तीन-तीन, चार-चार बार बात हो चुकी है। इस समय बीपीसीएल और इसके बारे में दो बातें हैं और लोगों की अलग-अलग राय हैं और उन रायों के बारे में जो भी सदन में कहा जा रहा है, सरकार इसको जरूर देखेगी, विचार करेगी परंतु बीपीसीएल और इसके बारे में राय रखना यह एक बात है।

केवल घाटे की कम्पनीज बेची जाएं या मुनाफे वाली बेची जाएं, यह दूसरी बात है। यह पर अलग-अलग तरह की बातें हो रही हैं। अगर केवल घाटे की बेचो, मुनाफे की न बेचो, लेकिन पंजाब में सारी मुनाफे की बेच दो, कर्नाटक में मुनाफे की बेच दो, वैस्ट बंगाल में मुनाफे वाली बेच दो।

श्री बसुदेव आचार्य : यह बात सही नहीं है। ...(Interruptions) Not a single profit-making State public undertaking is being disinvested. Dr. Malhotra, do not mislead the House. ...(Interruptions)

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, जब मैं बोल रहा हूँ, तो ये क्यों बीच में व्यवधान डाल रहे हैं। आप इन्हें रोकें।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाएं।

श्री बसुदेव आचार्य : लेकिन ये असत्य बोल रहे हैं। ...(Interruptions) He is misleading the House. Not a single profit-making State public undertaking has been disinvested in West Bengal. I challenge. ...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Let Dr. Malhotra complete. Please sit down.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Sunil Khan, please sit down.

...(Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : Do not mislead the House. ...(Interruptions)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : वैंस्ट बंगाल में सबसे पुराना होटल इन्होंने फ्रेंच कम्पनी को बेच दिया, बिजली का निजीकरण कर दिया और पानी का करने जा रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : बेचा कहाँ है ? ...(Interruptions)

SHRI SOMNATH CHATTERJEE : Sir, I think, the Chief Whip of the ruling Party must have little respect for truth. What is all this? ...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Shri Somnath Chatterjee, I understand. Let him speak.

...(Interruptions)

SHRI BASU DEB ACHARIA : He does not know. ...(Interruptions) हाउस में सच बात बतानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपे बैठिए।

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : केरल में, कर्नाटक में विनिवेश किया जा रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। यह जो दो कम्पनीज के बारे में बात कह रहे हैं, मंत्री महोदय को कहा कि इस पर सरकार विचार कर लें, इसको देख ले, यह बात समझ में आती है, लेकिन कोई व्यक्ति खड़े होकर यह कहे कि देश बेच दिया, देश बेचा जा रहा है, तो यह सही बात नहीं है। (व्यवधान) Please let me say so now. I take strong objection to that. ...(Interruptions)

SHRI CHANDRA SHEKHAR : You are selling the country. (Interruptions)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : चन्द्रशेखर जी अगर आप यह कह रहे हैं, then, you started selling the country. ...(Interruptions) आपने शुरू किया था कम्पनीज को बेचना। (व्यवधान)

SHRI CHANDRA SHEKHAR : Mr. Speaker, Sir, I want a parliamentary Committee to be set up to find out whether he is speaking untruth or (Interruptions) Mr. Speaker, let a Committee be appointed to find out whether I sold a single company or he is speaking untruth. ...(Interruptions)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : देश को बेचा जा रहा है, यह जो इल्जाम लगाया जा रहा है, यह सही नहीं है। कोई भी देश को नहीं बेच सकता। देश को बेचने का काम इन लोगों ने किया था, वह भी देश जानता है। जिन्होंने सोना गिरवी रखा था, उनके बारे में भी देश जानता है। आप पूरी बहस करें, यह समझ में आता है, परंतु देश बेच दिया, सब कुछ बेच दिया इस सरकार ने, यह असत्य बात है। इस मुद्दे पर पूरी बहस होनी चाहिए। (व्यवधान)

MR. SPEAKER: I am on my legs. Please sit down.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: This is not the issue on the agenda of our today's work. This issue was permitted to be raised only because notices for Adjournment Motion were given by three hon. Members. I have allowed them to speak. I have now understood the importance of the subject. There are arguments. If I can argue on the issue, I am going to take the issue to the Business Advisory Committee as early as possible. During discussion, people can make their views clear. When the subject is raised in the House, the hon. Minister will give the reply and if his reply is not satisfactory, we can find out some other way by which we can go ahead with this subject before the House. It was also discussed yesterday whether any company is to be disinvested is a matter within the purview of the Parliament or within the purview of the Government and the hon. Minister for Disinvestment gave a detailed reply on that. If the Members do not agree with that reply, they can always have their say in the House on the day when this issue will be discussed.

But there are a number of Members who want to raise other issues during 'Zero Hour'. How can we deprive those Members from raising their issues? Therefore, let us now take the notice for Adjournment Motion on POTA.

SHRI CHANDRA SHEKHAR : Mr. Speaker, I rise only to give a personal explanation. ...(Interruptions)

MR. SPEAKER: I have permitted him because he wants to give a personal explanation.

...(Interruptions)

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : आपने कहा कि हमने देश को बेच दिया। You said, "You are selling the country."

SHRI CHANDRA SHEKHAR : 'You' means, the Government is selling away the country.

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : We take objection to that.

SHRI CHANDRA SHEKHAR : Dr. Malhotra said that I had started selling away the country. It is a personal

accusation against me.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : मैंने भी यही कहा था कि आपकी गवर्नमेंट की तरफ से शुरू हुआ। If this is selling the country, then it had started during Shri Chandra Shekhar's Government. ...*(Interruptions)*

SHRI CHANDRA SHEKHAR : Let me complete. I said, in the very beginning, that this statement of the Government that I had started disinvestment of the type that they are doing now is totally incorrect. I said that we allowed disinvestment of

loss-making companies, whose shares were to be sold to the financial institutions of the Government.

DR. VIJAY KUMAR MALHOTRA : We will discuss it.

MR. SPEAKER: Let him complete.

SHRI CHANDRA SHEKHAR : Mr. Speaker, is it same as what they are going to do today? If Dr. Malhotra's assertion is correct, I am ready to face the Privileges Committee. Otherwise, Dr. Malhotra should withdraw his words or should face the Privileges Committee. You may refer the matter to the Privileges Committee.

डॉ.विजय कुमार मल्होत्रा : सर, इन्होंने कहा कि आप देश को बेच रहे हैं। मैंने कहा है कि यह इनकी गवर्नमेंट के टाइम में शुरू हुआ। I stand by my words that disinvestment had started during Shri Chandra Shekhar's Government. That is all. ...*(Interruptions)*

MR. SPEAKER: Please sit down. I do not think that arguments can work in this way.

...*(Interruptions)*

MR. SPEAKER: Shri Chandra Shekhar, you have made your stand clear. Let the Privilege Notice, if necessary, come to me and I will take a decision on that.

SHRI CHANDRA SHEKHAR : Mr. Speaker, Sir, in my whole career of 40 years in Parliament, I have not said a word which I had to withdraw later. In 40 years, there is not one instance. I have not made any personal accusation against anybody. I do not make any personal accusations. He said that it had started in my Government's time. I asked him that if it had started in my time, then in what way it had started. He should confine to that. He has not confined to that. They are selling companies to the private entrepreneurs, foreign companies and foreign multinationals. ...*(Interruptions)*

MR. SPEAKER: This is more than enough. Now, I give the floor to Shri Ramji Lal Suman. This issue, which he wants to raise, is also important. ...*(Interruptions)*

SHRI TARIT BARAN TOPDAR (BARRACKPORE): When the Minister is here, why are we reducing his power by not allowing him to respond now?

MR. SPEAKER: I do not have any objection if he wants to respond now.

SHRI TARIT BARAN TOPDAR : These are all his companies and, therefore, he should respond. This is a matter of procedure.

अध्यक्ष महोदय : सुमन जी को बोलने दीजिए।

SHRI BASU DEB ACHARIA : I have also given the notice for Adjournment.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, सदन की भावना को देखते हुए विनिवेश पर रोक लगवा दीजिए।
